अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन: भारतीय दृष्टिकोण, रणनीति और भविष्य

दिग्विजय सिंह

ऊर्जा के लिए महज अकेले या खोज के द्वारा आगे नहीं बढ़ा जा सकता इसके लिए हमें परंपरागत और आधुनिक दोनों तरह की सहभागिता चाहिए। सहभागिता का तात्पर्य प्राय: गठबंधन से होता है और गठबंधन मानवता, विकास और समावेशिता की सतत आशा जगा सकते हैं। भारतीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जुड़ाव के साथ आर्थिक और रणनीतिक विकास के तहत सौर ऊर्जा को एक ऊंची छलांग के तहत आगे बढ़ा रहा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री ने विश्व में भारतीय ऊर्जा की निविदा को उद्घोषित किया है। भारतीय उपभोग भी बढ़ रहा है इस वजह से हमें अधिक सतत ऊर्जा की आवश्यकता है अत: घरेलू और वैश्विक सौर योजना को स्वीकार्य करना अनिवार्य है

> *"विश्व के कई देशों में उच्च सौर विकिरण की संभावना व्याप्त है। हम इन सभी देशों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा सौर ऊर्जा की उपयोगिता बढ़ाई जा सके। इन सभी देशों में अपार शक्ति और क्षमताएं हैं अपनी ऊर्जा जरूरतों को तलाश करने का जो सौर ऊर्जा के माध्यम से संभव हो पाएगा।"*
>
> —श्री नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री)

वैश्वीकरण के दौर में ऊर्जा समस्त वैश्विक संभावनाओं और चुनौतियों का केंद्र विंदु है। ऊर्जा की जरूरत आज वैसे ही है जैसे भोजन, पानी, कपड़ा, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की है। दुर्भाग्वश आज भी दुनिया के आबादी का एक अहम हिस्सा 21वीं सदी के मुख्य आविष्कारों का आनंद उठाने से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट यह दर्शाती है कि दुनिया का हर पांचवां व्यक्ति आज भी आधुनिक बिजली का उपयोग नहीं कर पाता है, जबकि तीन बिलियन की आबादी के घरों में विद्युतीकरण की आपूर्ति होने के बावजूद भी वो रसोई के कामों के लिए लकड़ी, उपले, कोयला तथा अन्य परंपरागत ऊर्जा पर निर्भर हैं। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2016 में पेरिस में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पूर्व ही घोषणा कर दी थी कि, 'पाप किसी ने भी किया हो, गलती किसी की भी हो, भारत मानवता के कल्याण में अपना योगदान देगा। मैं सवा सौ करोड़ भारतीयों की ओर से दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि आज पर्यावरण के समक्ष जो संकट खड़ा हुआ है, उस पाप में हमारी कोई भूमिका नहीं है।' ऋग्वेद की ऋचाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत की परंपरा में हजारों वर्ष पहले कहा गया है कि भगवान सूर्य चल और अचल सभी वस्तुओं की आत्मा हैं।

21वीं सदी के शुरुआत से भारत की विदेश नीति में हो रहे व्यापक बदलाव का प्रभाव 'ऊर्जा कूटनीति' के क्षेत्र पर भी व्यापक रूप से पड़ा है। किसी भी देश की विदेश नीति की सफलता का पैमाना यह होता है कि इसके द्वारा देश के सभी पहलुओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सुरक्षा के सभी आयाम को सुरक्षित एवं संवर्धित किया जा सके। औद्योगिक विकास की दिशा में बढ़ते हुए विकासशील भारत के लिए इस सदी में सबसे बड़ी समस्या एवं चुनौती है इस विकास के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता। भारत अपने विकास के लिए हमेशा से प्राकृतिक तेल पर आधारित रहा है ऐसे में नए ऊर्जा स्रोत की ओर ध्यान देना अत्यावश्यक है। भारत को अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में अभी से सतर्क रहना होगा। इसके लिए ऊर्जा क्षेत्रों में व्यापक संबंधों एवं समझौतों की आवश्यकता विभिन्न देशों से है। ऐसे में ऊर्जा के क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेश नीति में कूटनीति का धारदार होना अत्यावश्यक है। मौजूदा सरकार के आने के बाद यह स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि भारतीय कूटनीतिक क्षमता सभी दृष्टिकोण से काफी प्रभावी हुई है। इसका एक जीवंत उदाहरण है आई.एस.ए जिसके माध्यम से भारत पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का एक नया आयाम स्थापित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है।

भारतीय परंपरा में सूर्य को सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसी संदर्भ

लेखक नोएडा स्थित एमिटि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। ईमेल: dgvj.sngh@gmail.com

ऊर्जा क्षेत्र का अगुआ ही बना है दुनिया का नेता

वैश्विक राजनीति में यदि कूटनीतिक संबंधों की हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1648 से होती है जबसे संप्रभु राष्ट्र विश्व-राजनीति के प्रमुख अंग बने। 1648 को गुजरे आज तकरीबन 350 वर्ष हो चुके हैं परंतु तब से लेकर आज तक महज दो अवसर ही ऐसे आये हैं जब किसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वही प्रभुता हासिल की है जो कि आज कहीं-न-कहीं अमेरिका की है।

यूरोप की राजनीति में 1660 से 1713 तक फ्रांस का दबदबा था चूंकि तत्कालीन समय में अफ्रीकी एवं एशियाई देशों का उभार नहीं हुआ था। अत: यूरोप की राजनीति ही विश्व की राजनीति मानी जाती थी। यह वैश्विक वर्चस्व का पहला उदाहरण है।

इस वर्चस्व का दूसरा उदाहरण ब्रिटेन से प्राप्त होता है। जिसने समुद्री व्यापार के जरिये 1860 से 1910 तक अपनी विक्टोरियाई शासन का सूर्य संपूर्ण विश्व पर प्रकाशित करता रहा। 1910 तक जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसी ताकतें ब्रिटेन के खिलाफ उठ खड़ी हुई और इन्होंने उसकी अपराजेयता को अवरुद्ध किया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला करके पुन: वैश्विक परिदृश्य में अपनी अपराजेयता सिद्ध की।

किंतु समय के साथ राजनीति के आयाम भी बदलते हैं। अत: अब प्रभुता या दबदबे को स्थायी रखने का कारण महज सैन्य शक्ति या व्यापार न होकर अपनी ऊर्जा की जरूरतें व अन्य देशों की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने की शक्ति हो गई।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी युद्ध या तनाव के माहौल उत्पन्न हुये उनका कहीं-न-कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध ऊर्जा जरूरतों या ऊर्जा संसाधनों पर अधिकार से था। शीत युद्ध हो, प्रथम खाड़ी-युद्ध हो या द्वितीय खाड़ी युद्ध हो अथवा क्यूबा मिसाइल संकट हो या अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप इन सबका संबंध कहीं-न-कहीं ऊर्जा जरूरतों से है।

अत: समकालीन वैश्विक राजनीति में हम यह देखते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता और इसकी आपूर्ति ही कहीं-न-कहीं अब देशों की विदेश नीति को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् व 21वीं सदी के प्रथम दशक तक का समय तेल व कोल ऊर्जा से संबंधित रहा है। ये दोनों ही ऊर्जा के संगठक ऐसे हैं जिनकी कि प्राकृतिक उपलब्धता निश्चित है और अत्यधिक दोहन की वजह से ये इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि बहुत जल्द ही संचित ऊर्जा स्रोत के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

अब बात इस तथ्य पर आकर रुक जाती है कि अपनी मानवीय, औद्योगिक, राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अब किस ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर हों जो कि हमारी सतत् बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता को अबाध रूप से पूर्ण कर सके। तब इस प्रश्न के उत्तर में हम एकमात्रा सौर ऊर्जा को विकल्प के तौर पर पाते हैं जो कि ऊर्जा का अक्षय और स्वच्छ तथा सतत् प्रदान करने वाला स्रोत है। वैश्विक राजनीति में अब 21वीं सदी के मध्य का युग उस देश का ही होगा जो इस अक्षय ऊर्जा को उत्पादित करने व इसके उत्पादन से संबंधित नीति-निर्माण पर अपनी प्रभुता हासिल कर।

1648 के बाद हम देखते हैं कि विश्व पर पहले फ्रांस फिर इंग्लैण्ड व उसके पश्चात् अमरीका का वर्चस्व बना रहा जिसमें कभी-कभी रूस ने भी स्वयं को स्थापित करने की कोशिश की परंतु वह इसमें सफल न हो सका। परंतु समकालीन समय में अमरीका के समक्ष अब चीन व भारत जैसे सशक्त देश उभर रहे हैं जो कि वैश्विक पटल पर न केवल अपनी जरूरतों को स्वयं से पूर्ण कर लेने में सक्षम हो रहे हैं वरन् एशियाई व अफ्रीकी देशों में व्याप्त यूरोपीय व अमेरिका की वर्चस्वता को तोड़ते हुये वहां भी अपनी प्रभुता को स्थापित कर रहे हैं।

भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ईसा के निर्माण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने सशक्त नेतृत्व का परिचय देकर वैश्विक राजनीति में एशियाई प्रभुता का आगाज किया है। चूंकि वर्तमान वैश्विक राजनीति में चाहे मानवीय विकास हो या औद्योगिक विकास हो सभी के लिए ईंधन के तौर पर ऊर्जा की अति आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अक्षय ऊर्जा के तौर पर सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है।

भारत महज सौर ऊर्जा ही नहीं वरन ऊर्जा के अन्य सभी क्षेत्रों में भी असियान, अपेक, यूरोप तथा अमेरिका सभी देशों व क्षेत्रीय संगठनों से ऊर्जा के क्षेत्र में कूटनीतिक संबंध स्थापित कर वैश्विक पटल पर अपनी ऊर्जा क्षमता के द्वारा एक नई एशियाई प्रभुता का आगाज करना चाहता है ताकि समकालीन वैश्विक राजनीति उत्तर-दक्षिण व दक्षिण-दक्षिण जैसे संवादों से मुक्ति प्राप्त करके एक सर्व समावेशी विश्व बन सके जिससे भारत अपने 'वसुधैव कुटुम्बकम' के लक्ष्य को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान करने में सफल हो सके।

में अंतर्राष्ट्रीय सौर समझौते के तहत भारत ने सौर ऊर्जा पर एक बड़ा दांव लगाया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सौर कूटनीति के तहत आह्वान किया है कि, ''आईये, सूर्य को हम मिलकर भविष्य के प्रकाशवर्षक के रूप में बदलें।''

पेरिस में आयोजित यूएन जलवायु परिवर्तन बैठक में भारतीय नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर समझौते को शुरू करने पर जोर दिया, जो नई दिल्ली के बड़े सौर दांव से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वृहत भू-राजनीतिक निहितार्थ हो सकता है। भारत जैसा विकासशील देश जो प्रचुर सूर्यप्रकाश में धनी है, लेकिन विद्युत ऊर्जा की कमी के कारण अभिशापित है। यद्यपि वह इस ओर प्रयासरत है कि अपनी कमियों को दूर कर तथा अपने ऊर्जा संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के द्वारा स्वयं को वैश्विक ऊर्जा के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभारें।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)

आईएसए सौर ऊर्जा क्षेत्र में धनी राष्ट्रों का एक कल्पित संगठन है, जो अपनी विशेष ऊर्जा क्षमता को परिभाषित करते हुए एक सामान्य व समन्वित माध्यम द्वारा ऊर्जा रिक्तांकों को पहचानते हुए, सौर सहयोग के लिए एक प्लेटफार्म तैयार करता है। यह अन्य संगठनों जैसे आईआरएनए व अन्य के कार्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। बल्कि

इसका कार्य एक ऐसे समूह को तैयार करना व सहक्रिया को विकसित करना है जो उसके प्रभावों का अनुपूरक हो और जो प्रभावों को केन्द्रीय रूप में प्रभावी बना सकें।

लक्ष्य व दृष्टांत

इस उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, आईएसए का लक्ष्य व दृष्टिकोण सौर संसाधनों में परिपूर्ण देशों के मध्य एक सहयोगात्मक प्लेटफार्म प्रदान करना है, जहां वैश्विक समुदाय जिसमें द्विपक्षीय व बहुपक्षीय संगठन, निगम से संबंधित लोग, उद्योग व हिस्सेदार शामिल हों, जो आईएसए के सदस्य देशों के मध्य सुरक्षित, सुविधाजनक, वहनयोग्य, न्यायसंगत व पोषणीय स्तर पपर सौर ऊर्जा उपयोग को सामान्य रूप में संभव बना सकें।

वस्तुनिष्ठ

इसका अतिशय आत्मविश्वास से पूर्ण वस्तुनिष्ठ एक ऐसे सामूहिक मंच का निर्माण करना है जो सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के बढ़ते परिनियोजन के लिए है तथा उससे ऊर्जा सुरक्षा व निरंतरता के विकास को बढ़ावा देना संभव होगा ऊर्जा तक सरल/बेहतर पहुंच ग्रामीण व सुदूरवर्ती इलाकों में बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देगा। अपने उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आईएसए ने 5 मुख्य क्षेत्रों को रेखांकित किया है:

क) सौर प्रौद्योगिकी और सौर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, ताकि गरीब व वैश्विक पर्यावरण में आय उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके।

ख) ऐसे परियोजनाओं व कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिससे सौर क्षेत्रों के प्रयोग को बढ़ावा मिले।

ग) पूंजी की लागत को कम करने के लिए नवपरिवर्तनशील वित्तीय तंत्र का विकास।

घ) सामान्य जानकारी से संबंधित एक ई-पोर्टल का निर्माण।

ड) सदस्य राष्ट्रों में सौर प्रौद्योगिकी और आर एण्ड डी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।

उपरोक्त विवर्णित क्षेत्रों का संदर्भ केवल ग्रिडों से जुड़े सौर ऊर्जा से नहीं वरन् ऑफ-ग्रिड व विकेन्द्रित यंत्रों को बढ़ावा देने से भी है। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए आईएसए ने निम्नलिखित नियामक तय किए हैं-

i) संयुक्त शोध, विकास व प्रदर्शन, सूचना

सौर गठबंधन बनते ही मिलने लगे अन्य सहयोग भी

भारत निरंतर ऊर्जा रणनीति सहभागिता के द्वारा बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण का दावा करता रहा है, जबकि इसके साथ ही वह पाश्चात्य और शेष अन्य विश्व के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है जिसके तहत उठाया गया एक कदम *भारत का नवीकरणीय ऊर्जा कांग्रेस* है। इसका उद्देश्य मेगावॉट से गीगावॉट में स्थानांतरण है। यह निवेशकों, डेवलपर और नीति निर्धारकों के सम्मिलन का एक मंच है जो स्पष्ट दृष्टिकोण और नवीन केस अध्ययनों को समझ सकें। भारत ने लगातार ऐसे प्रयास किये हैं, जिसके द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के बड़े पक्षकारों के साथ आगे बढ़ा जा सके। सौर ऊर्जा, नागरिक परमाणु ऊर्जा, जल-विद्युत और उष्मीय सहयोग में भारत का उदय, भारत के लिए एक अच्छा पल है। 2015 के ऐतिहासिक पेरिस समझौते से अलग *वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा* के सुधार के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास उद्देश्य कार्यक्रम को भी देखा जा सकता है।

विश्व बैंक द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक प्रतिवेदन के द्वारा यह आंकलन किया गया है कि विकासशील विश्व के 89 मिलियन लोगों के पास उनके घर में अब कम से कम एक सौर प्रकाशित उपकरण है। भारत के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बनाये गये माहौल ने निम्न और मध्यम प्रकार के प्रतिष्ठानों के विकास और बढ़ोत्तरी को एक मंच प्रदान किया है। 2014 से स्वच्छ ऊर्जा पहुंच का नया नेटवर्क इस तरह के प्रतिष्ठानों के लिए एक सयुंक्त आवाज बनता जा रहा है जो नीति निर्माताओं, निवेशकों, तकनीक विकासक और प्रशिक्षण प्रदान करने वालों के साथ-साथ बहुसंख्यक हिस्सेदारों के मध्य कार्य कर रहा है और जो देश के बढ़ते ऊर्जा पहुंच क्षेत्र को मदद देने के साथ ही मजबूत भी कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2040 तक भारत की तेल उत्पादों की मांग 10 मिलियन बैरेल प्रति दिन ढ़ाई गुना से अधिक हो जायेगी जो किसी भी देश द्वारा सर्वाधिक वृद्धि वाला क्षेत्र होगा। इस वजह से यह सहभागिता भारत के लिए यह आवश्यक बना देता है कि वह नवाचार और रिसर्च तथा विकास के क्षेत्र को बढ़ावा दे और भारत अवश्य ही इसमें वैश्विक रिक्तता को न केवल भरे वरन इसे प्रभावी बनाये।

वर्तमान मूल्य पर्यावरण में भारत का सर्वाधिक विक्रय बिंदु तब आया जब यह तेजी से बढ़ती और खत्म होती डॉलर की मांग को भुनाने तक पहुंच गया और बराबरी तक पहुंच का माध्यम बना। जब यह गैस के क्षेत्र में आता है तो जिसमें कि भारत स्वयं भंडारक है मूल्य से परे, प्रवाहमयी बाजार के विकास और अवसंरचना के वितरण के क्षेत्र में समान रूप से संकटग्रस्त दिखता है।

भारत के लिए 2015 परमाणु सहयोग के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के जनवरी 25-27 के दौरान परमाणु प्रशासनिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गये जिसके तहत परमाणु क्षतिपूर्ति अधिनियम 2010 को आगे बढ़ाया गया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत के एनपीसी II एवं अमेरिका के वेस्टिंग हाउस के मध्य भारत में 6 परमाणु संयत्र (एपी-1000) स्थापित गुजरात में करने की पुष्टि की गई है।

वहीं रूस एवं फ्रांस के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अप्रैल में मोदी के फ्रांस दौरे के समय एल एंड टी एवं एवेरा के मध्य जैतपुर परमाणु संयत्र के खर्च नियंत्रण पर भी हस्ताक्षर हुआ। वहीं 22 दिसंबर 2015 को रूस में भी दोनों पक्षों के बीच भारत में परमाणु संयत्र स्थापित किये जाने पर हस्ताक्षर किया गया। प्रधानमंत्री के कनाडा दौरे में अगले पांच वर्षों तक यूरेनियम खरीद के समझौते पर सहमति बनी।

जल विद्युत, ताप विद्युत एवं सागर जल विद्युत के क्षेत्र में भारत के द्वारा विभिन्न देशों के मध्य समझौते, भारत को इस क्षेत्र की नयी शक्ति बनाया है। इन सभी प्रयासों के द्वारा भारत परंपरागत ऊर्जा राजनीति में अपनी आधिपत्य स्थापित करने की और तीव्र गति से अग्रसर है अर्थात् इस क्षेत्र में भारत विश्व का प्रतिनिधित्व सहयोग, समझौते एवं परस्पर सामंजस्य के तहत करता रहेगा।

व ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमता-निर्माण, सहयोगी प्रौद्योगिकी हब और संचार के लिए सहयोगात्मक संबंधों का विकास।

ii) सदस्य राष्ट्रों के स्थानीय शेयरधारकों द्वारा सौर ऊर्जा के संकलन, फैलाव, स्वदेशीकरण, ज्ञान ग्रहण प्रौद्योगिकी व हुनर का विकास।

iii) सामान्य मानदंडों, जांच, निरीक्षण संबंधी प्रोटोकॉल के विकास के लिए विशेषज्ञ समूहों का निर्माण।

iv) ऊर्जा सुरक्षा व ऊर्जा प्रयोग को समुच्चियत व सुगठित करने के लिए विभिन्न देशों के मध्य साझीदारों को बढ़ाना।

v) सदस्य राष्ट्रों के मध्य कार्यकारियों या प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।

vi) सदस्य राष्ट्रों के मध्य संयुक्त उपक्रम के विकास के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना।

vii) नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र में तथा नवपरिवर्तनशील वित्तीय विकास के लिए नए वित्तीय तंत्र को स्थापित करना। तथा

viii) अन्य बहुद्देशीय संस्थाओं जैसे- आईआरईएनए, आरईईईपी, आईईए व अन्य के साथ सहयोग स्थापित करना।

संचालन ढांचा

आईएसए द्वि-रेखीय क्षेत्र में सौर-ऊर्जा से परिपूर्ण देशों के मध्य बहुद्देशीय संगठन के रूप में प्रस्तावित है। आईएसए के शासकीय ढांचे में एक असेम्बली, एक परिषद् और एक सचिवालय प्रस्तावित है, जिसमें असेम्बली निर्देशन और सलाह के लिए, सचिवालय कार्यों के संचालन के लिए है।

कार्यक्रम व परियोजना

आईआरईएनए, आरईईईपी, जेईए, आरईएन21, यूएन के विभिन्न अंग, जैसे बहुपक्षीय संगठन, द्विपक्षीय संगठन, कॉर्पोरेट, उद्योग व अन्य शेयर धारकों द्वारा सौर ऊर्जा की उपयोगिता को आईएसए को महत्व दिया है-

i) सौर प्रकाश के ब्रह्मांडीय वितरण मजबूत बनाने के लिए आईएसए के सदस्य देशों के साथ कार्य करना।

ii) सदस्य राष्ट्रों के मध्य सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली व कार्यों का आदान-प्रदान ताकि वित्तीय यंत्रों का ढांचा बनाकर बाधाओं को कम व निवेश को बढ़ाया जा सके।

iii) विद्युतीय तंत्रों के विकास के लिए परिप्रेक्ष्यों का आदान-प्रदान।

iv) आईएसए सदस्य देशों के मध्य उद्योग सहयोग को प्रोत्साहन।

v) छात्रों/अभियंताओं/नीति निर्धारकों के मध्य ट्रेनिंग कार्य का ख़ाका तैयार करना।

वित्तीय संपोषणीयता

भारत सरकार का इस क्षेत्र में कुल सहयोग 400 करोड़ का है। भारत सरकार अवसंरचना के विकास व आवर्तक खर्च के रूप में 175 करोड़ दे रही है। यह 5 वर्षों के लिए है 2016-17 से 2021-22 तक। जब तक नए कार्यालय का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक अपने कार्य के लिए सूर्य भवन का इस्तेमाल करेगी।

भारत अपने उन ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के जीवन की गुणवत्ता में तेजी से सुधार कर सकता है जोकि अभी विद्युत ग्रिड की कमी की वजह से अंधकारमय हैं यह सहभागिता उन बहुसंख्यक देशों के लिए प्रस्तावित किया गया है जो इसी तरह की समान समस्या से ग्रसित हैं जिसका कारण ऊर्जा तक न्यून गति से पहुंच है। जैसे एक किसान जो अपनी उत्पादकता और आय में वृद्धि के लिए तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकता अथवा शुद्धिकरण के अत्यधिक खर्चीले होने के कारण स्वच्छ पेय जल की कमी अथवा प्रकाशीय और प्रशीतन सहित आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की कमी अथवा आधुनिक उपकरणों और प्रकाश तथा पंखे के साथ स्कूलों की अपर्याप्त संख्या। ये देश अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर एक आवाज चाहते हैं जोकि उनकी इन समस्याओं के लिए आवाज उठा सके और उपाय ढूंढ सके। इन देशों के लिए भारत एक आवाज बन सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यत: देशों में ग्रामीण गरीबों के लिए सौर स्रोत निधि के साथ सौर ऊर्जा के ऊर्जा सेवा में व्याप्त व्यापक पहुंच को उपलब्ध करने का यंत्र बनेगा, किंतु कौन वर्तमान समय में इस प्रमुख ऊर्जा स्रोत की क्षमता को और इसे ग्रामीण जीवन के बदलाव के रूप में एक अवसर के तौर पर पहचानने में भूल कर रहा है? यह आईएसए के विभिन्न सहभागी देशों में यह दिखायेगा कि कैसे सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग, उपयुक्त तकनीक और सौर ऊर्जा के द्वारा निर्मित उपकरण, खर्च को कम करेगा, विदेशी विनिमय बचाएगा और बगैर अनावश्यक भारी निवेश के ऊर्जा अवसंरचना को विस्तारित करेगा। इसके अतिरिक्त यह रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी में मदद करेगा और उद्योग अनुसंधान के हस्तांतरण को बढ़ावा देगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग के एक आवश्यक मुद्दे को उठाने की आवाज बनेगा।

सौर ऊर्जा सहयोग, निवेश और सहभागिता भारत की क्षेत्र में कूटनीति को एक व्यापक आयाम प्रदान कर सकती है। सौर सहभागिता न केवल आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण है वरन् यह भारत को ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अगुआ देश के रूप में उभरने का अवसर भी देगी जो रणनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। नए क्षेत्र तथा वृहद सहभागिता में निरंतरता तथा सहभागिता में जीवंतता ये तीनों तथा भारत के लिए अत्यधिक आवश्यक वस्तु हैं। देश को सौर सहभागिता के मुद्दों को घरेलू तथा वैश्विक दोनों स्तर पर प्राथमिकता के तौर पर रखना होगा।

ऊर्जा सुरक्षा नवीन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रमुख बिंदु है और सौर ऊर्जा सर्वाधिक स्वीकार्य और सतत् (अक्षय) स्रोत है इसलिए एक देश के लिए इसमें शोध और विकास तथा इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में आर्थिक निवेश को प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाता है।

सामान्यत: एशिया और मुख्यत: दक्षिण एशिया में आईएसए के तहत वृहद ऊर्जा सहभागिता को भारत मजबूत और व्यापक तरीके से रखता है। वैश्विक स्तर पर भारत को एशिया में सौर ऊर्जा के विमर्श, सहभागिता और निवेश में सशक्त भूमिका अदा करनी चाहिए। ताकि हर संभव देशों में वह अपनी पहुंच बना सके और सौर ऊर्जा में सेवा प्रदाता तथा संबंधित वस्तु प्रदाता बन सके और ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ ही इस क्षेत्र में विकसित देशों की व्याप्त वर्चस्वता को तोड़ सके। ❑